विविध सिविल

माननीय एस.एस. संधावालिया और एस.पी.

गोयल जे.जे. के समक्ष

रण सिंह कल्सन, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1973 *का* 2760

3 फरवरी, 1978।

भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम *1955* - विनियम *5* (5) - *दक्षता को पार करना*], बार - क्या *पूर्व प्रतिकूल प्रविष्टियों को समाप्त करने का प्रभाव पड़ता है - ऐसी प्रविष्टियों* पर भविष्य की पदोन्नति के समय विचार किया जा सकता *है - वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ प्रतिनिधित्व - क्या केवल एक मौखिक आदेश द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।*

यह माना गया कि प्रतिकूल प्रविष्टियां जो किसी सरकारी कर्मचारी को दक्षता बार में रखने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं मानी जाती हैं, स्पष्ट रूप से उसकी बर्खास्तगी के आरोप का आधार नहीं बन सकती हैं, लेकिन जब उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन किया जाता है तो अलग-अलग विचार होते हैं। दक्षता पट्टी को पार करने की अनुमति देते समय, संबंधित प्राधिकारी को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर एक राय बनानी होती है कि क्या दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति नहीं देने के लिए इस तरह की प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं, जबकि पदोन्नति प्रतिकूल रिपोर्टों की अनुपस्थिति के आधार पर नहीं बल्कि सकारात्मक योग्यता के आधार पर की जाती है। दक्षता पट्टी को पार करने की अनुमति देने और पदोन्नति देने के पैमाने अलग-अलग हैं। पूर्व में जो पर्याप्त है वह उत्तरार्द्ध के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हो सकता है। प्रतिकूल रिपोर्ट को दक्षता सीमा को पार करने के लिए निवारक के रूप में नहीं माना जाता है और पदोन्नति के दावे

को अस्वीकार करने के लिए इसे ध्यान में रखा जा सकता है। इस प्रकार, भविष्य की पदोन्नति के लिए एक लोक सेवक के मामले पर विचार करते समय, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह खुला है कि वह उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सेवा के पूरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखे।

(पैरा 7 और 8)

शादी लाल *बनाम* उपायुक्त और अन्य 1974 (1) एसएलआर 217 को खारिज कर दिया।

यह नहीं कहा जा सकता है कि वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ एक अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के लिए सरकार को एक मौखिक आदेश पारित करना होगा। कोई भी प्रशासनिक आदेश पारित करते समय सरकार अर्ध-न्यायिक तरीके से कार्य करने और एक सुविचारित तर्क पारित करने के लिए बाध्य नहीं है।

आदेश। निष्पक्ष खेल और न्याय की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है यदि रिकॉर्ड से यह दिखाया जा सकता है कि प्रतिनिधित्व को ठीक से निपटाया गया था और गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। (पैरा 11 और 13)।

एम.के. बख्शी *बनाम* पंजाब राज्य 1971 (1) एसएलआर 119 को खारिज कर दिया गया।

माननीय न्यायमूर्ति एस पी गोयल द्वारा 8 फरवरी, 1977 *को मामले में शामिल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति एस पी गोयल की टीआरई डिवीजन बेंच ने अंततः 3 फरवरी,* 1978 को मामले का फैसला किया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *और* 227 *के तहत संशोधित याचिका मे प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहत दी जाए: -*

(१) सर्टिओरेरी रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादियों 1, 2, 14 *और* 15 *और* 16 *को निर्देश दिया जाए कि वे उस समय याचिकाकर्ता की वरिष्ठता से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अदालत के समक्ष रखें, जब उसके कनिष्ठों को मई में गैर-*

आईपीएस कैडर में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। 1972; *दिसंबर,* 1972; *जनवरी ^फरवरी; और अगस्त, 1973, और 1 जनवरी*, 1973 *तक की अवधि के लिए चयन सूची तैयार करने के संबंध में याचिकाकर्ता के मामले के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी न करने से संबंधित रिकॉर्ड को भी उत्तरदाताओं की आक्षेपित कार्रवाई के अवलोकन के बाद रद्द कर दिया जाए;*

(२) मंडामस रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादियों 1, 2 और 15 *को निर्देश दिया जाए कि वे गैर-आईपीएस कैडर में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें, जिस तारीख से उनके कनिष्ठ श्री वीके कपूर को पदोन्नत किया गया था।* 1965 *से 31 मार्च,* 1966, *1 नवंबर।* 1966 *से 31 मार्च, 1965, 1 अप्रैल*, 1967 से 31 मार्च, 1968 और 8 दिसम्बर, 1970 से 31*;* मार्च*,* 1971

(३) 1 अप्रैल, 1965 *से 31 मार्च की अवधि के लिए चार गोपनीय रिपोर्टों का कोई संदर्भ दिए बिना आईपीएस पदोन्नति विनियमों के तहत सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए उत्तरदाताओं 1,* 2 और 16 *को निर्देश देते हुए एक रिट जारी की जाए।* 1966, *1 नवंबर;*(क) क्या यह सच है कि 196 से मार्च, 1967 और 1 अप्रैल*, 1967 से 31 मार्च, 1968 और 1 दिसम्बर*, 1970 से *31 मार्च, 1971* तक के लिए *क्या होगा;*

(४) एक रिट ऑफ मैंडमस की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादियों 1, 2, 14 और *16* को 1 जनवरी तक तैयार और अनुमोदित चयन सूचियों के *प्रीपा राशन को पुन खोलने का निर्देश दिया जाए*/भारतीय पुलिस सेवा *(पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955* के तहत 1972 और 1 जनवरी, *1973* और याचिकाकर्ता को सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद नए सिरे से सूची तैयार करें और याचिकाकर्ता का मामला भी चयन समिति के समक्ष रखा गया है और चयन समिति को निर्देश दिया जाए कि वह 1 अप्रैल की अवधि से संबंधित चार गोपनीय रिपोर्टों

की अनदेखी करने वाले याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करे। 1965 *से 31 मार्च, 1966, 1 नवम्बर*, 1966 *से 31 मार्च, 1967; 1* अप्रैल; 1967 *से 31 मार्च;* 1968 *और दिसम्बर,* 1970 *से 31 मार्च;* 1971;

(५) इस मामले की परिस्थितियों में यह न्यायालय उचित समझे जाने वाला कोई अन्य उपयुक्त रिट, निदेश या आदेश जारी किया जाए;

(६) इस याचिका की लागत; याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाए,

याचिकाकर्ता की ओर से वकील *आनंद सरूप और वकील एमएल बंसल पेश हुए।*

चंद्र सिंह, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए।*

निर्णय

एस. पी. गोयल, जे.

(एक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह याचिका मुख्य रूप से श्री शादी लाल बनाम भारत में इस न्यायालय के दो एकल पीठ के निर्णयों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए भेजी गई थी। *गुड़गांव के उपायुक्त और अन्य* (1) और *जसवंत सिंह, बरार* वी. *पंजाब राज्य और अन्य* (2) इस मुद्दे पर कि क्या एक बार किसी सरकारी कर्मचारी को दक्षता सीमा पार करने की अनुमति दी जाती है, तो उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करते समय उससे पहले की प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखा जा सकता है but.as याचिका पूरी तरह से निपटान के लिए हमारे समक्ष है, तो पक्षकारों की संबंधित दलीलों और दलीलों पर पहले ध्यान दिया जा सकता है।

(दो) याचिकाकर्ता को पंजाब लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रतियोगी

परीक्षा के परिणामस्वरूप 21 जून, 1963 को पंजाब पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(तीन) आयोग और 21 दिसंबर, 1965 को इस तरह की पुष्टि की। वर्ष 1971 में याचिकाकर्ता का वेतनमान 400-30-580/40-720-40-800-50-1000/50-1150 रुपये था, और उसे 2 फरवरी, 1971 को पहली दक्षता सीमा को पार करना था। तथापि, उन्हें 1 मार्च, 1965 से 31 मार्च, 1966, 1 नवम्बर, 1966 से 31 मार्च, 1967, 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1967, 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 और 8 दिसम्बर की अवधि के लिए चार गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर दक्षता पट्टी में उनके प्रस्तावित ^ होल्डिंग के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 1970 से 31 मार्च, 1971 तक। उक्त नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था और उन्हें 27 दिसंबर, 1971 के आदेश के तहत दक्षता बार में रोक दिया गया था। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे सरकार ने 7 जून, 1972 के आदेश के तहत अनुमति दे दी। इस बीच, प्रतिवादी नंबर 3 वीके कपूर, जो याचिकाकर्ता से जूनियर थे, को पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और उनकी पदोन्नति के खिलाफ याचिकाकर्ता ने 17 जून, 1972 को एक अभ्यावेदन दिया। जबकि यह अभ्यावेदन अभी भी निर्णय के लिए लंबित था, गैर-आईपीएस में पुलिस अधीक्षकों के कुछ और पद। कैडर खाली हो गया और प्रतिवादी संख्या 7, 8 और 9, जो याचिकाकर्ता से जूनियर थे, को क्रमशः 26 फरवरी, 1973, 31 जनवरी, 1973 और 16 जनवरी, 1973 से पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया। बेशक, पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता पर विचार करते समय, उक्त चार रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था। याचिकाकर्ता ने हरियाणा के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक जेसी वाचर और रोहतक के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कल्याण रुद्र के खिलाफ *दुर्भावनापूर्ण* आरोपों के अलावा अपने से कनिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति को इस आधार पर चुनौती दी है कि पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करते समय दक्षता सीमा पार करने

की अनुमति देने की तारीख से पहले की प्रतिकूल रिपोर्टों को अवैध रूप से ध्यान में रखा गया था। उनकी अनदेखी और प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदनों को एक गैर-भाषी आदेश द्वारा उचित विचार के बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था।

(चार) याचिकाकर्ता की दूसरी चुनौती दिसंबर 1972 में भारतीय पुलिस सेवा कैडर में पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा तैयार किए गए भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियमन 5 के तहत चयन सूची में अपना नाम शामिल नहीं करने के खिलाफ निर्देशित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण प्रवर समिति द्वारा उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था और यदि विचार किया गया, तो उनके नाम को खारिज कर दिया गया था। चार गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है। यह तर्क दिया गया कि सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले विनियमन 4 के तहत जारी किए गए भारत सरकार के निर्देश, वैधानिक नियमों के विपरीत अवैध और शून्य थे। चार गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करने पर पहले से ही ऊपर देखे गए आधारों पर हमला किया गया है।

(पाँच) हरियाणा राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में, यह स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता की दक्षता बार में उसे रखने के आदेश के खिलाफ अपील को इस आधार पर अनुमति दी गई थी, कि 8 दिसंबर से 31 मार्च, 1971 की अवधि के लिए गोपनीय रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता है और उसे 2 फरवरी 1971से दक्षता बार पार करने की अनुमति दी गई थी। याचिका में की गई अन्य सामग्री कथनों से इनकार कर दिया गया था और यह कहा गया था कि कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्ति और चयन सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए उनके नाम पर विधिवत विचार किया गया था, लेकिन (चार गोपनीय रिपोर्टों सहित उनके ओवर-ऑल रिकॉर्ड के आधार पर फिट नहीं पाया गया)। याचिकाकर्ता का यह आरोप भी गलत था कि गोपनीय रिपोर्टों के खिलाफ उनके अभ्यावेदन को बिना सोचे-समझे और एक गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा खारिज कर दिया

गया है और यह कहा गया था कि उचित प्राधिकारी द्वारा उन पर विधिवत विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक (प्रतिवादी संख्या 2) जेसी वाचर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक कल्याण रुद्र (प्रतिवादी संख्या 15) ने अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों से इनकार करने के लिए अलग-अलग हलफनामे दायर किए।

(एक) जैसा कि इस फैसले के उद्घाटन में देखा गया था, उनकी वरिष्ठता के खिलाफ सबसे बड़ा हमला यह था कि पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करते समय दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति देने की तारीख से पहले की गोपनीय रिपोर्टों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था। इस विवाद के लिए मुख्य निर्भरता पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर रखी गई है । *दीवान चुन्नी लाल,* (3)। इस फैसले पर भरोसा करते हुए, *श्री शादी लाल के मामले* (सुप्रा) में तुली, जे ने कहा कि "1 नवंबर, 1964 से पहले याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को पदोन्नति के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि उसे 1 नवंबर, 1964 को देय दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, जिसने पिछली सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों को माफ कर दिया था: हालांकि, *जसवंत सिंह बराड़ के मामले में शर्मा, जे द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया* था (सुप्राडी जिसमें सुप्राड शामिल है) यह माना गया था कि जब किसी लोक सेवक के मामले को उसके सहयोगियों की तुलना में भविष्य में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी के लिए यह खुला है कि वह लोक सेवक की सेवा के पूरे रिकॉर्ड को उसकी तुलनात्मक / योग्यता का आकलन करने के लिए विचार करे।

(दो) दीवान चुन्नी लाल के भाषण में सबइंस्पेक्टर दीवान चुन्नी लाल को 12 अक्टूबर, 1949 को तय किए गए एक आरोप का जवाब देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें 1941 से 1948 तक सेवा में रहने के दौरान उनकी अक्षमता और ईमानदारी की कमी को दर्शाते हुए उनके गोपनीय चरित्र रोल के उद्धरण सामने आए थे और प्रथम दृष्टया अपना जवाब प्रस्तुत करने

के लिए कहा गया था। पंजाब पुलिस नियमों के पैरा 16.25 (2) में परिकल्पित अक्षमता का आरोप। उन्हें वर्ष 1944 में दक्षता पट्टी को पार करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1941 और 1942 में प्रविष्टियों के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने राय दी कि 1944 से पहले की रिपोर्टों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उन्हें उस वर्ष दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी। यह अकल्पनीय है कि यदि अधिकारियों ने 1941 और 1942 की गोपनीय रिपोर्टों में निहित बेईमानी और अक्षमता के आरोप को गंभीरता से लिया होता, तो वे इसे नजरअंदाज कर सकते थे और 1944 में दक्षता सीमा पार करने के लिए अधिकारी के मामले की सिफारिश कर सकते थे। इस फैसले का स्पष्ट रूप से इस सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है कि क्या उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करते समय किसी लोक सेवक के चरित्र रोल में प्रतिकूल प्रविष्टियों को उस तारीख से पहले ध्यान में रखा जा सकता है जब उसे दक्षता सीमा पार करने की अनुमति दी गई थी। जैसा कि उड़ीसा *राज्य बनाम उड़ीसा में* कहा गया है। *सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य,* (4) एक निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह क्या तय करता है। किसी निर्णय में जो सार होता है, वह उसका अनुपात होता है, न कि वहां पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही इसमें किए गए विभिन्न अवलोकनों से तार्किक रूप से क्या अनुसरण होता है। *इसलिए, दीवान चुन्नी लाल के मामले* (सुप्रा) में निर्णय से, यह वैध रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि दक्षता पट्टी की अनुमति देने वाले आदेश से पहले की प्रविष्टियां *सभी उद्देश्यों के लिए* गैर-आवश्यक हैं।

(तीन) जिन प्रतिकूल प्रविष्टियों को किसी सरकारी कर्मचारी को दक्षता बार में रखने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं माना जाता है, जाहिर है कि मैं उनकी बर्खास्तगी के आरोप का आधार नहीं बन सकता हूं, लेकिन जब उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन किया जाना होता है तो अलग-अलग विचार होते हैं। दक्षता पट्टी को पार करने की अनुमति देते समय, संबंधित प्राधिकरण को किस आधार पर एक राय बनानी होगी**?**

पिछले रिकॉर्ड में बताया गया है कि क्या इतनी बड़ी प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं कि दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है जबकि पदोन्नति प्रतिकूल रिपोर्टों की अनुपस्थिति के आधार पर नहीं बल्कि सकारात्मक योग्यता के आधार पर की जाती है। जैसा कि *जे एस एस वेंकटरन वी में देखा गया* है। *उड़ीसा राज्य और अन्य* (5) दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति देने और पदोन्नति देने के पैमाने अलग-अलग हैं। पूर्व के लिए जो पर्याप्त है वह उत्तरार्द्ध के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हो सकता है। प्रतिकूल रिपोर्ट को दक्षता सीमा को पार करने के लिए निवारक के रूप में नहीं माना जाता है और पदोन्नति के दावे को अस्वीकार करने के लिए इसे ध्यान में रखा जा सकता है। *दीवान चुन्नी लाल* के मामले में टिप्पणियों के बारे में, यह माना गया था कि वे अलग-अलग थे और उस मामले के अजीब तथ्यों पर आधारित थे और इस व्यापक प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते थे कि दक्षता पट्टी को पार करने से पहले प्रतिकूल प्रविष्टि को मिटा दिया जाता है।

(चार) जहां तक *श्री शादी लाल के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय का* संबंध है, विद्वान न्यायाधीश ने विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि दीवान चुन्नी लाल के मामले में *सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के फैसले को देखते हुए* 1 नवंबर से पहले याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टियां, 1964 में, जब उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार करते समय दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, तो *दीवान चुन्नी लाल के मामले* में तथ्यों या उस उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना ध्यान में नहीं रखा जा सकता था जिसके लिए यह माना गया था कि प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जा सकता है। *दीवान चुन्नी लाल के मामले* के उचित विश्लेषण पर, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि जिस तारीख से किसी लोक सेवक को दक्षता सीमा पार करने की अनुमति दी जाती है, उससे पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं या उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करते समय उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा विचार *है कि श्री शादी लाल* (सुप्रा) के मामले में सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया

था और भविष्य में पदोन्नति के लिए लोक सेवक के मामले पर विचार करते समय, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह खुला है कि वह उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सेवा के पूरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखे। नतीजतन, याचिकाकर्ता की पहली दलील में कोई दम नहीं है कि उसे दक्षता सीमा पार करने की अनुमति देने की तारीख से पहले प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए गलत तरीके से फंसाया गया था।

(पाँच) यह हमें याचिकाकर्ता के अगले तर्क पर लाता है कि उसकी वरिष्ठता के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन सरसरी तौर पर थे। बिना सोचे-समझे बिना अस्वीकृत आदेश द्वारा। याचिका के पैरा 16 में इस संबंध में लगाए गए आरोपों को सरकार द्वारा दायर लिखित बयान में खारिज कर दिया गया था और यह कहा गया था कि मामले पर पूरा विचार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए सरकार द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक 'एम' के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:

> श्री रण सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, दिनांक 17 जून, 1972 और 1 अगस्त, 1972 को उन्हें अधीक्षक के पद पर पदोन्नत न करने के लिए अभ्यावेदन
>
> सरकार ने विचार के बाद पुलिस को खारिज कर दिया है।

(छः) विद्वान वकील का तर्क है कि आदेश सरकार द्वारा अपने दिमाग के प्रयोग को नहीं दर्शाता है और न ही इसमें अभ्यावेदनों को अस्वीकार करने का कोई कारण है और इस तरह एक गैर-भाषी आदेश होने के नाते इसे रद्द किया जा सकता है। इस विवाद के लिए उप *आबकारी एवं कराधान आयुक्त एम. के. बख्शी पर भरोसा जताया गया है*। *पंजाब राज्य और अन्य* (6), *भारत संघ और अन्य मदन लाल, हेड क्लर्क, राजेंद्र अस्पताल पटियाला,* (7) डी, *लाल चंद परगल* वी। *निदेशक सीडी और एमईएस और अन्य* (8), *और करतार सिंह* वी। *दिल्ली प्रशासन और अन्य* (9).

(सात) लाल चंद परगव मामले *(सुप्रा) में,* जम्मू और कश्मीर सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 25 (2) के प्रावधानों पर विचार करने पर, पूर्ण पीठ ने कहा कि उक्त नियम की भाषा का अर्थ है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ कर्मचारी को पारित करने का कारण दिया जाना चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि नियुक्ति प्राधिकारी ने वास्तव में अपना दिमाग लगाया था। हालांकि, पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि भले ही नियुक्ति प्राधिकारी आदेश में कारणों को दर्ज नहीं करता है, यह नियमों के नियम 25 (2) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि समकालीन या पूर्ववर्ती रिकॉर्ड जिसके आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति का आदेश पारित किया गया है) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पदोन्नति के लिए कारण दिए गए हैं और नियुक्ति प्राधिकारी ने अपना दिमाग लगाया है। इस पर कार्यवाही ऐसे अभिलेख का आधार जिसमें पदोन्नति के आधार शामिल हों । इस निर्णय के अनुसार, इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि कारणों को पदोन्नति के क्रम में दर्ज किया जाना चाहिए और यह सरकार द्वारा दिमाग के आवेदन को दिखाने के लिए पर्याप्त होगा यदि पदोन्नति के आदेश वाली फाइल से पता चलता है कि पदोन्नति आदेश पारित करते समय पूरे समकालीन रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था। इसलिए, यह निर्णय याचिकाकर्ता के लिए शायद ही कोई मदद करता है। इसी तरह, मदन लाल के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय तथ्यों से अलग है और इसका प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है। उस मामले में, मदन लाल की वरिष्ठता को उन्हें सुनने का कोई अवसर दिए बिना बदल दिया गया था। नतीजतन, यह माना गया कि चूंकि किसी सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता तय करने से उसकी सेवा में पदोन्नति की भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे अपनी वरिष्ठता को संशोधित करने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इस निर्णय में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि सरकार को सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता तय करते समय या उसके अभ्यावेदन को अस्वीकार करते समय कोई मौखिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है

(आठ) *एमके बख्शी के मामले* (सुप्रा) में, याचिकाकर्ता ने अपनी वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ और उड़ीसा *राज्य बनाम उड़ीसा पर* भरोसा करते हुए एक अभ्यावेदन दिया । *डॉ(मिस) बीनापानी देई,* (10), तुली, जे. ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह एक तर्कसंगत आदेश पारित करके *अर्ध-न्यायिक* तरीके से उस प्रतिनिधित्व पर विचार करे और निर्णय ले, जिसे एक मौखिक आदेश कहा जाता है। हमारे विचार में *डॉ(मिस) बीनापानी के देई के मामले* (सुप्रा) पर भरोसा पूरी तरह से गलत था। उस मामले में, सरकार ने एक जांच की और इसके परिणामस्वरूप, डॉ (मिस) बीनापानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें कारण बताने के लिए कहा गया कि उनकी जन्म तिथि 4 अप्रैल क्यों न स्वीकार की जाए। 1907. उन्होंने जवाब में प्रस्तुत किया कि उनकी जन्म तिथि सही दर्ज की गई थी, लेकिन सरकार ने 27 जून, 1963 के अपने आदेश में उनकी जन्म तिथि 16 अप्रैल, 1907 निर्धारित की। इस आदेश को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। उनकी दलील को स्वीकार करते हुए जे. सी. शाह, जे. ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "राज्य को निस्संदेह नहीं रोका गया था, केवल इसलिए कि सेवा रजिस्टर में पहले प्रतिवादी की तारीख दर्ज की गई थी, यदि ऐसा था तो जांच करने से।

(नौ) बच्चे के जन्म के बारे में जांच करने और फिर से जांच करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद थे। लेकिन परिणाम या जांच के आधार पर साथी का निर्णय न्याय की मूल अवधारणा के अनुरूप है। इसलिए, मुझे यह आदेश देने का आदेश दें कि हवाई अड्डे में काम करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह केवल न्याय और निष्पक्षता के मानदंडों के अनुसार ही हो सकता है। यदि कोई न्यायाधीश पक्षकारों के बीच कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के सभी रूपों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की जाती है, एनआईएस का पक्ष रखने या बचाव पक्ष

को सही करने या नष्ट करने का अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान करे। यदि किसी प्राधिकारी पर उसके पूर्वाग्रह के लिए भरोसा करने की कोशिश की जाती है, तो या उस उद्देश्य के लिए जांच करने वाले व्यक्ति को उस मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसे पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, उसके समर्थन में सबूत। नियम यह है कि एक पक्ष जिसके पूर्वाग्रह के लिए एक बुजुर्ग को पारित करने का इरादा है, सुनवाई का हकदार है, न्यायिक न्यायाधिकरणों और व्यक्तियों के निकायों पर लागू होता है जिन्हें नागरिक परिणामों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था के मूलभूत नियमों में से एक है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधिकारियों द्वारा मनमाने अधिकार के प्रयोग से बचाया जाता है। इसलिए न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य उस प्रकृति से उत्पन्न होगा जो कार्य करने का इरादा है, इसे सुपर-एडेड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह को तय करने और निर्धारित करने की शक्ति है, तो न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य ऐसी शक्ति के प्रयोग में निहित है। यदि न्याय की अनिवार्यता को नजरअंदाज किया जाता है और किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए एक आदेश दिया जाता है, तो आदेश एक निरर्थकता है।

(दस) उक्त टिप्पणियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उस मामले में सरकार ने कुछ जांच की थी और उस जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, डॉ (मिस) बीनापानी को न तो उस सामग्री के बारे में सूचित किया गया था और न ही उन्हें सरकार द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का खंडन करने का कोई अवसर दिया गया था। इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि की गई कार्रवाई से सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

प्राकृतिक न्याय। इसलिए, इस मामले के तथ्यों में वरिष्ठता के निर्धारण के मामले के लिए कोई समानता नहीं है। *डा (मिस) बीनापानी* के मामले (सुप्रा!) में ऊपर उल्लिखित टिप्पणी सरकार द्वारा की गई जांच के संदर्भ में की गई थी और इसे वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जिसमें किसी भी जांच का आयोजन या किसी भी सामग्री का संग्रह शामिल नहीं है। इसलिए, *डा (मिस) बीनापानी* के मामले में की गई टिप्पणियों को तर्क की किसी भी प्रक्रिया द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है और न ही उक्त टिप्पणियों के आधार पर यथोचित रूप से माना जा सकता है कि वरिष्ठता के निर्धारण के खिलाफ अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के लिए, सरकार को एक मौखिक आदेश पारित करना होगा। नतीजतन हम *एमके बख्शी के मामले* में फैसले से सहमत होने में असमर्थ हैं और इसे खारिज किया जाता है।

(बारह) *करतार सिंह के मामले* (सुप्रा) में, प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ किए गए अभ्यावेदन को एक मौखिक आदेश पारित किए बिना खारिज कर दिया गया था, जिसे सच्चर, जे द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रद्द कर दिया गया था: -

> "प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के निपटान के मामले में सरकार द्वारा नियमों और निर्देशों का एक बहुत विस्तृत सेट बनाया गया है। विशिष्ट अनुदेश और नियम बनाए गए हैं जिसमें समीक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया गया है और क्या वह रिपोर्टिंग अधिकारी से सहमत या असहमत है। आई.जी.पी. द्वारा बनाए गए नियम 13,17 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध अभ्यावेदन

देने का प्रावधान है। भारत सरकार ने भी अपने ज्ञापन में प्रतिकूल प्रविष्टि के खिलाफ प्रतिनिधित्व की तात्कालिकता और महत्व पर जोर देते हुए प्रावधान किया है कि उन्हें प्रतिनिधित्व की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर तय किया जाना चाहिए। यह निर्विवाद है कि प्रतिकूल प्रविष्टि का कर्मचारी के सेवा कैरियर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसे हल्के ढंग से नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस पर सरकारी कर्मचारी के भविष्य के कैरियर पर निर्भर हो सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया गया था। निष्पक्षता की कम से कम यह मांग है कि सक्षम प्राधिकारी उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर अपना दिमाग लगाएगा और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं से निपटने के लिए एक मौखिक आदेश पारित करेगा और कम से कम उन कारणों को संक्षेप में भी इंगित करेगा जो राजी हुए थे।

प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करना। लेकिन इस मामले में जो कुछ भी किया गया है वह यह है कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा एक गूढ़ आदेश पारित किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि उसके अभ्यावेदन पर विचार किया गया है और खारिज कर दिया गया है। अब यह उन अभ्यावेदनों को निपटाने का सबसे असंतोषजनक तरीका है जो याचिकाकर्ताओं के करियर के इस तरह के एक महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि प्रतिवादी नंबर 2 को कानून की अदालत के रूप में एक निर्णय लिखना चाहिए, लेकिन यहां एक अभ्यावेदन था जिसमें रिपोर्ट की प्रामाणिकता, रिपोर्ट की अनुपस्थिति, समीक्षा अधिकारी को

> भेजे जाने, नियमों और निर्देशों का पालन न करने को चुनौती दी गई थी। निश्चित रूप से इन प्रमुख बिंदुओं को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा निपटाया जाना चाहिए, और यह उनके आदेश को पढ़ने से स्पष्ट होना चाहिए।

इन टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि अभ्यावेदन में गोपनीय रिपोर्टों को *दुर्भावनापूर्ण* और नियमों और निर्देशों का पालन न करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के पास अभ्यावेदन देने का वैधानिक अधिकार था जिसे सरकार द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों के अनुसार निपटाया जाना था। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि "विचार और अस्वीकार" शब्दों के साथ प्रतिनिधित्व को खारिज करना इसके निपटान का सबसे असंतोषजनक तरीका था। इसलिए, इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले में सहायक नहीं होगा, लेकिन हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि सरकार को अपने प्रशासनिक कार्यों को करते समय न्यायिक रूप से कार्य करने या बोलने का आदेश पारित करने की आवश्यकता है जब भी इस तरह के आदेश के नागरिक परिणाम होते हैं।

(तेरह) हमारे संज्ञान में कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं लाया गया है जिसमें कहा गया हो कि सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता के खिलाफ अभ्यावेदन को एक मौखिक आदेश द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है। सिद्धांत रूप में, हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि कोई भी प्रशासनिक आदेश पारित करते समय सरकार अर्ध न्यायिक तरीके से कार्य करने और एक अच्छी तरह से तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। हमारे विचार में, निष्पक्ष खेल और न्याय की आवश्यकता पूरी हो जाएगी यदि रिकॉर्ड से यह दिखाया जा सके कि प्रतिनिधित्व को ठीक से निपटाया गया था और गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार वर्तमान मामले में भी, उन्हें ऊपर देखी गई चार

प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण हटा दिया गया था और लिखित बयान में, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके अभ्यावेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया था और प्रतिकूल कारणों से खारिज कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, हमें याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता कि उसके अभ्यावेदन को उचित दिमाग के बिना और लाकोनिक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(चौदह) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि चार प्रतिकूल प्रविष्टियों को उच्चतम प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था - जो उनके मामले में याचिकाकर्ता को उनके संचार से पहले सरकार थी और इसलिए, उक्त प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने गोपनीय रिपोर्टों के बारे में समेकित निर्देशों में निहित सरकार के कुछ निर्देशों पर भरोसा किया और याचिका के पैराग्राफ 19 में उनके द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण का अर्थ नियुक्ति प्राधिकरण या प्राधिकरण है, जिसके लिए निंदा की सजा के खिलाफ प्रतिनिधित्व मौजूदा नियमों के तहत आता है। विद्वान वकील का तर्क पूरी तरह से गलत है क्योंकि जिस पत्र में सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरण को "नियुक्ति प्राधिकारी" या प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसके लिए निंदा की सजा के खिलाफ प्रतिनिधित्व 24 जून, 1972 को जारी किया गया था, जबकि आक्षेपित प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 1971 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्देशों का उक्त (प्रतिकूल रिपोर्ट) पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अपने लिखित बयान में, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब चरित्र सूची में उन प्रविष्टियों को किया गया था, तो पुलिस महानिरीक्षक गोपनीय रिपोर्टों को मंजूरी देने के

लिए पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.17 (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी थे। चूंकि यह विवादित नहीं है कि उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों को तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा याचिकाकर्ता को उनके संचार से पहले अनुमोदित किया गया था, इसलिए हमें याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई दम नहीं मिला कि प्रतिकूल प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और वैध रूप से दर्ज किया गया था।

(पंद्रह) याचिकाकर्ता का दूसरा दावा कि सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण प्रवर समिति द्वारा उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था और यदि विचार किया गया तो उक्त चार गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर खारिज कर दिया गया था, हालांकि, अच्छी तरह से स्थापित है। भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उपखंड (5) में यह अपेक्षा की गई है कि यदि चयन, समीक्षा या संशोधन की प्रक्रिया में राज्य पुलिस सेवा के किसी सदस्य की जगह लेने का प्रस्ताव किया जाता है, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगी। जुलाई के एक सरकारी निर्णय द्वारा दिनांक 28, 1965 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उन सभी पात्र अधिकारियों, जिनके मामले प्रवर समिति के समक्ष रखे जाते हैं, के संबंध में प्रायोजक प्राधिकारी है, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने याचिकाकर्ता को 'सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र' जारी करने से इनकार कर दिया। प्रवर समिति की रिपोर्ट के अवलोकन से, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के नाम को सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार नहीं किया गया था, हालांकि इसमें यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता को योग्यता के आधार पर भी फिट नहीं पाया गया था। *गुरदयाल सिंह फिजी बनाम फिजी* मामले में हाल ही में एक खंडपीठ के

फैसले में *'सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र' की आवश्यकता वाले निर्देशों को अवैध* घोषित कर दिया गया था। *पंजाब राज्य और अन्य,* (11), निम्नलिखित शब्दों में:-

> "विनियम 3 से 7 स्व-निहित नियम हैं जो चयन समिति के गठन के लिए पूरी प्रक्रिया, पात्रता के लिए योग्यता, उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करने आदि को निर्धारित करते हैं। इन विनियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अखंडता प्रमाण पत्र संकल्प 1-1 की आवश्यकता है जो केवल एक कार्यकारी निर्देश है। विनियम काफी विस्तृत हैं और चयन का पूरा तरीका दिया गया है और चयन सूची में व्यक्तियों को लाने के लिए योग्यता-सह-वरिष्ठता मुख्य आधार है। विनियमों में यह कहीं भी निर्धारित नहीं है कि पदोन्नति के लिए पात्रता प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कार्यकारी निर्देशों के तहत यह आवश्यकता वैधानिक नियमों के विपरीत है। इसने समिति पर अपने विवेक से प्रतिबंध और सीमाएं लगा दी हैं। इसके अलावा, यह कहीं भी निर्धारित नहीं है कि अखंडता प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाना है। संकल्प 1.1 में किसी मापदंड का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए यह कुछ मामलों में मनमानी और अनुचितता को जन्म दे सकता है। इसलिए, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रस्ताव 1.1 उन विनियमों का उल्लंघन करता है जिन्हें कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे विनियम 4 और 5 के उल्लंघन के रूप में निरस्त किया जाता है।

(सोलह) वीजन बेंच के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि प्रवर समिति ने याचिकाकर्ता को चयन सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए विचार करने से अवैध रूप से इनकार कर दिया था। हालांकि, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अखंडता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता के मामले पर गुण-दोष के आधार पर भी विचार किया गया और प्रवर समिति द्वारा खारिज कर दिया गया। निस्संदेह, प्रवर समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर भी अयोग्य पाया गया था, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि यह पारित टिप्पणी यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता के मामले पर वास्तव में गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया था क्योंकि प्रवर समिति द्वारा उसकी वरिष्ठता के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था जैसा कि विनियम 5 के उप-खंड (5) में अपेक्षित है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि सेवा के कुछ पात्र सदस्यों की अनदेखी करने के कारणों को दर्ज किया गया था और यदि याचिकाकर्ता के मामले पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया होता तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसका नाम अन्य कथित सदस्यों के नामों और उसकी वरिष्ठता के लिए दर्ज कारणों में शामिल नहीं होता। इसलिए, हम याचिकाकर्ता की इस दलील से पूरी तरह सहमत हैं कि सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण प्रवर समिति द्वारा एचआईजी नाम पर विचार नहीं किया गया और *गुरदयाल सिंह फिजी के मामले (सुप्रा)* में निर्णय को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि प्रवर समिति ने याचिकाकर्ता के नाम को चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार करने से अवैध रूप से इनकार कर दिया है।

(सत्रह) नतीजतन, इस याचिका को ऊपर की सीमा तक अनुमति

नहीं दी जाती है और प्रतिवादी संख्या 1 और 14 को एक निर्देश जारी करने का आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को वर्ष 1973 के लिए तैयार चयन सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए विचार करें। याचिका की आंशिक सफलता को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एस.एस. संधावालिया, जे.-मैं सहमत हूं।

1. 1974 (1) एस.एल.आर. 217.
2. 1975 (द्वितीय) एस.एल.आर. 899.
3. ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 2086
4. ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 64 एल
5. (1971)1 एस.एल.आर.
6. (1971)2 एसएलआर 51.
7. ए.आई.आर. 1971 जे. और के. 108.
8. 1967 एस.एल.आर.
9. 1967 एस.एल.आर. 465.
10. 1977 एसएलडब्ल्यूआर 57

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक

होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy